

3.7.1.2 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू / गैर-दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार वर्ष 2014–15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रूप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में शामिल किया गया है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनानांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोड़ा, गधा, ऊँट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केंद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केंद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11168, वर्ष 2015–16 में 37486, वर्ष 2016–17 में 59113, वर्ष 2017–18 में 38219, वर्ष 2018–19 में 52908, वर्ष 2019–20 में 52704 एवं वर्ष



पशुधन की वृद्धि, प्रदेश की समृद्धि

पशुधन बीमा योजना-

- योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मरुषेषी भी शामिल हैं।
- यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।
- एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर किया जाता है।



जिसने भी पशुधन का बीमा कराया उसने निश्चिंता के साथ लाभ कराया



पशुधन बीमा योजना

अब तक 48 हजार 200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3 सालों में बीमा कंपनी को 6.949 करोड़ का प्रीमियन भुगतान किया गया है।

हितग्राहियों को अब तक 20.21 करोड़ रुपये दावा टाशि का भुगतान किया जा चुका है।



अब किसान पशुपालन अपना कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

- 1 हितग्राही 5 पशुओं का बीमा करा सकता है।
- मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना सभी ज़िलों में लागू है।
- योजना की क्रियान्वयन इकाई म.प्र. पशुधन एवं कुकुरुट विकास निगम हैं।



पशुधन की वृद्धि, प्रदेश की समृद्धि पशुधन बीमा योजना

प्रीमियम पर अनुदान

- गरीबी ऐखा के ऊपर वाले हितग्राहियों का 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश ॲपर राज्यांश 25-25 प्रतिशत शामिल हैं।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी ऐखा से नीचे वाले हितग्राहियों का 70 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश 40 प्रतिशत ॲपर राज्यांश 30 प्रतिशत शामिल हैं।